साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2019/78930

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

मुरैना, सोमवार 19-25 दिसंबर , 2022 वर्ष-5, अंक-4

मुरैना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

गांव-किसान-चौपाल का अखबार

आज़ादी के बाद जनता और अखबार के बीच एक और कड़ी जुड़ गई। यह कड़ी थी बाजार। बाजार ने अखबार को प्रोडक्ट बना दिया। प्रकाशक कंपनी में बदल गए। पाठकों को पता ही नहीं चला कि अखबारों ने उन्हें कस्टुमर मान लिया है। अखबारों की बाल्टी-मग्गे और जैकपॉट की स्कीम इस बात को साबित करती है कि समाचारों की दुनिया बदल चुकी है। इस शोर शराबे में धीरे-धीरे वंचितों, किसानों या कहें- ग्रामीण भारत की आवाज़ गुम हो गई। अखबार (टीजी) यानि टारगेट ग्रुप पर फोकस करने लगे हैं। गहन वन में रहने वाले आदिवासी, खेतों में हल चलाने वाले किसान, गांव देहात के लोग अखबारों के लिए अब जरूरी नहीं हैं। चौपाल पर होने वाली चर्चाएं सरकारों तक पहुंचाने का काम अब के अखबार ईमानदारी से नहीं करते। भारत की ग्रामीण आबादी के लिए नीति निर्धारण करने वाले लोग भी गांव को नहीं समझते, किसान को नहीं जानते। उनके लिए गांव सड़क का वह छोर है, जहां मील के पत्थर पर शून्य की संख्या ही दिखाई देती है।

शिवप्रताप सिंह जादौन
संपादक

अखबारों में अलग-अलग क्षेत्र की खबरों के कवरेज के लिए अलग से रिपोर्टर रखने की व्यवस्था है। व्यापार की खबरों के लिए बिजनेस रिपोर्टर, अपराध की खबरों के लिए क्राइम रिपोर्टर, यहां तक की धर्म-अनुष्ठान के लिए भी अलग से बीट व रिपोर्टर होते हैं। लेकिन किसानी या उद्यानिकी के लिए कहीं भी अलग से रिपोर्टर नहीं रखे जाते। ऐसे में जागत गांव हमार अखबार एक छोटा सा प्रयास है, जो चौपाल की बात को भोपाल तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। संयोग ही है कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्यप्रदेश के मुरैना लोकसभा क्षेत्र के औरेठी गांव के एक सामान्य किसान के पुत्र हैं। संयोग पर संयोग है कि जागत गांव हमार का यह संस्करण उसी मुरैना जिले के मुख्यालय से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे में बहुत सहजता से कहा जा सकता है कि यह अखबार किसान की आवाज सीधे केंद्रीय सत्ता तक भी पहुंचाएगा। इस अखबार की पहुंच चंबल संभाग की हर ग्राम पंचायत तक होगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन होगा। सरकार और जनता की बात परस्पर एक दूसरे तक सीधे पहुंच सकेगी। गांधी जी ने ग्रामीण भारत को ग्राम स्वराज्य की नींव पर खड़ा करने का जो सपना देखा था, उस सपने को बल प्रदान करेगा यह अखबार। ताकि प्रदेश के आखरी गांव का हर आखरी व्यक्ति भी कह सके कि- जागत गांव हमार।

किसानों को चुनावी सौगात देने की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार

अन्नदाता का ब्याज होगा माफ!

» उन किसानों के ब्याज का भुगतान करेगी जिन्हें बैंक ने माना डिफाल्टर

» 11 लाख डिफॉल्टर, 16 लाख अन्य किसानों पर सहकारी बैक का कर्ज

भोपाल। जागत गांव हमार

चुनावी साल में ऋणी किसानों को प्रदेश सरकार ब्याज माफी की सौगात दे सकती है। सरकार उन किसानों के ब्याज का भुगतान स्वयं करेगी जिन्हें बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इससे ऐसे ऋणी किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वे जल्दी ऋण मुक्त होकर दोबारा बैंक से कर्ज ले सकेंगे। जैसा कि किसानों को खेती-किसानी के कई कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। इसके कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बैंक उन किसानों को डिफाल्टर घोषित कर देता है जिससे वे आगे नया लोन नहीं ले पाते हैं। इन किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से बैंक द्वारा डिफाल्टर किए गए किसानों के ऋण पर ब्याज की रकम चुकाने की घोषणा की गई है। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा।

किसानों के हित में कई घोषणाएं

चुनावी साल में किसानों को उम्मीद है कि भाजपा सरकार फसल ऋण माफी कर देगी, क्योंकि सीएम शिवराज किसानों के हित में ब्याज माफी की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं। इसमें डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करने की बात भी कही गई हैं। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाये जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।

केवल मूलधन ही जमा करना होगा

मप्र सरकार की ओर से ब्याज माफी योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण बैंक से डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी का लाभ प्रदान करेगी। किसान के मूलधन चुकाने पर उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। योजना में 30 मार्च 2018 के पहले के कर्जदार किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा।

नौ हजार करोड़ का आएगा भार

सरकार कर्ज माफी करती है तो उसे मूल धन और ब्याज मिलाकर 24 हजार करोड़ बैंकों को देने पड़ेंगे। सिर्फ ब्याज माफ करती है तो 9 हजार करोड़ चुकाने होंगे। प्रदेश में 11 लाख डिफॉल्टर किसान हैं। 16 लाख अन्य किसानों पर सहकारी बैकों का कर्ज है। दोनों को मिलाकर 24 हजार करोड़ का कर्ज है। समितियों से नियमित रूप से 30 लाख किसान फसल ऋण लेते हैं।

किसानों को मिलेंगी कई और सौगातें

चुनावी साल में किसानों को कई अन्य सौगातें भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रुपए की वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऋण ब्याज माफी सहित किसानों के हित में कई कल्याणाकारी घोषणाएं की है।

बड़े तौल कांटे लगाए जाएंगे

राज्य के किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों की मरम्मत का कार्य होगा। मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने के साथ ही बड़े तौल कांटे लगाए जाएंगे। राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा। गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का कार्य किया जाएगा। जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य किया जाएगा। किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश सहित देशभर के किसानों ने किया कमाल, एमपी और यूपी में गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ोतरी

देश में गेहूं का तीन और तिलहन रकबा आठ फीसदी बढ़ा

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय किसानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। चालू रबी सीजन में गेहूं का क्षेत्रफल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले तीन फीसदी बढ़कर 286.5 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ने से यह बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन के 16 दिसंबर तक के क्षेत्रफल के लिए जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पिछले साल इसी अवधि तक गेहूं का क्षेत्रफल 278.25 लाख हेक्टेयर रहा था। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक में गेहूं का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले अधिक है जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा में गेहूं का क्षेत्रफल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कम बना हुआ है। गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ने और अनुकूल मौसम रहने के चलते इस साल गेहूं का उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

केंद्र ने रबी सीजन के क्षेत्रफल के आंकड़ों की दी जानकारी

बड़ी उपलब्धि

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 16 दिसंबर तक रबी सीजन के धान का क्षेत्रफल 12.64 लाख हैक्टेयर हो गया जो इसके पहले साल समान अवधि में 11.13 लाख हैक्टेयर रहा था। वहीं दालों का क्षेत्रफल पिछले साल के 134.01 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 139.68 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। चना का क्षेत्रफल 97.9 लाख हेक्टेयर हो गया है जो पिछले साल इसी अवधि में 94.97 लाख हेक्टेयर रहा था।

अच्छी कीमत की उम्मीद

तिलहन फसलों का क्षेत्रफल 97.94 लाख हेक्टेयर हो गया है जो पिछले साल समान अवधि में 90.51 लाख हेक्टेयर रहा था। रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों का क्षेत्रफल पिछले सला के 83.18 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 89.99 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60 फीसदी खाद्य तेल आयात करता है। पिछले दो साल से सरसों की कीमतों में इजाफा हुआ है और किसान बेहतर कीमत की उम्मीद में इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं।

बारिश ने बढ़ाया क्षेत्रफल

रबी सीजन में फसल बोवनी का कुल क्षेत्रफल 578.10 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है जो पिछले साल इसी अवधि में 552.28 लाख हेक्टेयर रहा था। मानसून की बारिश के सामान्य से अधिक समय तक होने के चलते मिट्टी में बेहतर नमी के चलते इस साल रबी सीजन का क्षेत्रफल अधिक रहने की संभावना है। जिसके चलते उत्पादन पिछले साल से अधिक रहने का अनुमान है। बहुत कुछ फरवरी और मार्च में तापमान के सामान्य रहने पर निर्भर रहेगा।

पिछले बर्ष का टूटा रिकॉर्ड

आंकड़ों के मुताबिक पिछले रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन रहा था जबकि उसके पहले साल गेहूं का क्षेत्रफल 10.95 करोड़ टन रहा था। पिछले साल मार्च के महीने में अचानक तापमान बढ़ने के चलते गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा था। हालांकि एक्पर्ट्स ने गेहूं का उत्पादन सरकारी आंकड़ों से कम रहने की संभावना जताई थी। सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद देश में गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो अनुमानों पर सवाल खड़ा करती है। बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत के चलते सरकार रबी मार्केटिंग सीजन में केवल 187.92 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद कर सकी थी जबकि लक्ष्य 444 लाख टन का रखा गया था।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसानों का अहम योगदान

हर खेत मिट्टी परीक्षण एंबुलेंस प्रयोगशाला सेवा होगी शुरू

» एफपीओ की वर्कशॉप में शामिल हुए कृषि मंत्री पटेल

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि आत्म-निर्भर भारत के निर्माण में किसानों का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्री पटेल भोपाल में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भू-उर्वरता को बनाए रखने के लिए हर खेत मिट्टी परीक्षण एंबुलेंस प्रयोगशाला सेवा शुरू की जा रही है। अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी जेएन कंसोटिया, संचालक कृषि प्रीति मैथिल नाईक, एमडी मंडी बोर्ड रश्मि, सीजीएम नाबार्ड एमडी मल्होत्रा और कृषि उत्पादक समूह के किसान मौजूद रहे।

हमारा देश कृषि प्रधान देश

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आत्म-निर्भर भारत निर्माण में कृषि और किसानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि आधारित रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार निरंतर किसान कल्याणकारी योजनाएं बना कर संचालित कर रही है।

खेत पहुंचेंगे कृषि अधिकारी

मंत्री ने कहा कि कृषि में रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है। राज्य सरकार ने मिट्टी क्षरण को रोकने के लिए किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने हर खेत मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। खेत एंबुलेंस में कृषि वैज्ञानिक के साथ कृषि अधिकारियों की टीम रहेगी, जो किसान के खेत में पहुंच कर ऑन स्पॉट यह बताएगी कि खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है और कितना नहीं करना है।

किसानों को मिल रही सब्सिडी

कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2019- 20 में केन्द्र सरकार 71 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी। अब यह बढ़ कर सवा दो लाख करोड़ रुपए हो गई है। पहले डीएपी की बोरी 19 सौ रुपए में मिलती थी। जिसमें किसान को 700 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी। अब डीएपी 3900 रुपए प्रति बोरी है, जिसमें सरकार 2700 रुपए सब्सिडी दे रही है।

एमएसपी पर बिकेगा चिकन, सदन में सांसद ने दिए जवाब

पोल्ट्री फार्मिंग के लिए केंद्र सरकार चला रही योजनाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

डेयरी व पशुपालन के साथ ही देश में एक बाद तबका पोल्ट्री पालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, आए दिन चिकन और अंडे को एमएसपी पर बेचने की बात की जाती है। सरकार पोल्ट्री पालन शुरू करने वालों के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में सरकार से कई सवाल किए। कोरोना वायरस के डर से लोगों ने चिकन और अंडे खाना बंद कर दिया था, इसी बात को लेकर सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी पूछा कि क्या सरकार साल 2019 और 2020 में कोविड के चलते मुर्गी पालन क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में जानती है, अगर हां तो राज्यवार नुकसान का आंकड़ा क्या है। साथ ही ये पूछा की क्या सरकार की चिकन बिक्री को लेकर

एमएसपी पर बेचने की कोई योजना है। केंद्रीय पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रुपाला ने लोकसभा में पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने पोल्ट्री व्यवसाय में नुकसान को लेकर कहा कि कई राज्यों में लॉकडाउन की वजह से अंडे, मुर्गे, मांस की बिक्री के साथ-साथ चारे की ढुलाई पर भी प्रतिबंध था, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर को भी नुकसान हुआ, लेकिन पशुपालन विभाग ने इस नुकसान का आकलन नहीं किया है। चिकन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाले सवाल पर पशुपालन मंत्री परशोत्तम रुपाला ने बताया कि फिलहाल सरकार चिकन पर एमएसपी निर्धारित करने पर विचार नहीं कर रही, क्योंकि ये एक जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है। देश के ज्यादातर इलाकों में पोल्ट्री अलग-अलग लागत होने के कारण बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ही चिकन की कीमतों का निर्धारण होता है।

50 फीसदी तक सब्सिडी

पशुपालन और डेयरी विभाग ने पोल्ट्री पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जून 2020 से 15000 करोड़ की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि लागू की जा रही है। इस योजना के तहत प्रोद्योकिकी रूप से सहायता प्राप्त कुक्कुट फार्म, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन संरचना और कुक्कुट चारा सयन्त्र शुरू करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पोल्ट्री फार्मों के स्थापना से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है।

पोल्ट्री फार्मिंग की योजनाएं

केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने साल 2020 से ही पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जारी की है, जिसके तहत डेयरी प्रोसेसिंग से लेकर मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मीट प्रोसेसिंग की मूल्य संवर्धन अवसंरचना और मवेशियों के लिए चारा संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए व्यक्तिगत उद्यमियों से लेकर निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठन और समेत दूसरे संस्थानों के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

किस्म और प्रसंस्करण की किसानों को दी जाएगी जानकारी

सीमैप मेलाः जहां पर मिलेगी औषधीय फसलों की जानकारी

भोपाल। अगर आप भी औषधीय और सुगंध फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ये आपके काम की खबर है। हर वर्ष की तरह इस बार फिर सीएसआरआई-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में 31 जनवरी को किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। सीएसआरआई-सीमैप के निदेशक डॉ. पीके त्रिवेदी बताते हैं कि सीमैप हर साल 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन करता है, जिसमें पूरे देश से पांच हजार से ज्यादा किसान आते हैं। लेकिप पिछले दो साल कोविड महामारी के चलते हमने किसान मेला को आयोजन पांच या दस दिनों के लिए किया था। क्योंकि कोविड का प्रतिबंध था। इस बार फिर हम 31 जनवरी को किसान मेला का आयोजन एक दिन के लिए कर रहे हैं, काफी बड़ा कर रहे हैं। इसमें पूरे देश से किसान आने वाले हैं। किसानों को मेडिसिनल और ऐरोमैटिक प्लांट की नई किस्में दी जाएंगी, साथ ही किसानों को एग्रोटेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। सीमैप पिछले करीब डेढ़ दशक से हर साल 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन करता आ रहा था, जिसमें यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, लेकिन दक्षिण भारत के की राज्यों के भारी संख्या में किसान शामिल होते थे। लेकिन कोविड महामारी के चलते पिछले 15 जनवरी से 5 फरवरी तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 4000 लोग शामिल हुए थे।

यूपी में देश की 80 फीसदी मेंथा की खेती

देश की 80 फीसदी मेंथा उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, चंदौली, सीतापुर, बनारस, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, चंदौली, लखीमपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, रायबरेली में इसकी खेती होती है। बाराबंकी को मेंथा का गढ़ कहा जाता है। यहां बागवानी विभाग के मुताबिक करीब 88000 हेक्टेयर में मेंथा की फसल लगाई जाती है। बाराबंकी अकेले प्रदेश में कुल तेल उत्पादन में 25 से 33 फीसदी तक योगदान करता है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह ने कहा

डिजिटल तकनीक से किसानों को बिचौलियों से मिली आजादी

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर सशक्त बनाया है। इससे वे कई तरह की परेशानियों से बच गए हैं और उन्हें लूट-भ्रष्टाचार व बिचौलियों से आजादी मिली है। यह बातें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहीं। वह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में बात कर रहे थे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा, किसानों की दी जाने वाली सहायता राशि डिजिटलीकरण की वजह से सरकार द्वारा अब सीधे किसानों तक पहुंचने लगी है, जिससे किसानों को कारोबार करने के नए अवसर मिले हैं और वे उनका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीज से बाजार तक की एक नई अवधारणा बनाई है, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक चमत्कार साबित हुआ है। इस मिशन ने किसानों की परिस्थियों और जीवन स्तर मे बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है।

1.74 करोड़ किसान ई-नाम मंडी से जुड़े

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1.74 करोड़ से ज्यादा देशभर के किसानों को ई-नाम मंडी के जरिए जोड़ा गया है। 2.36 लाख व्यापारों को ई-नाम के जरिए रजिस्टर्ड किया गया है, जिनके जरिए 2.22 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11.37 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है और इस योजना केजरिए इन किसानों के खाते में 2.16 लाख करोड़ रुपए सीधे जमा कराए गए हैं।

22.71 करोड़ कार्ड बनाए गए

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल क्रांति के बाद किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी काफी लाभ मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि सैटेलाइट के जरिए किसानों की फसल की देखभाल की गई। किसान उत्पादक संघ के तहत 3,855 से भी ज्यादा एफपीओ रजिस्टर्ड किए गए। सॉयल हेल्थ कार्ड के तहत 22.71 करोड़ कार्ड बनाए गए और देशभर में 11 हजार 531 टेस्टिंग लैब्स को मंजूदी दी गई।

अब खेती बाड़ी के साथ ही कर रहे दूसरे भी काम

हार नहीं मानी कान्हा से विस्थापित आदिवासियों ने

बंजर जमीन में कर रहे खेती, उगा रहे सब्जी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क से विस्थापित हुए आदिवासियों ने अपनी जगह के लिए दावा करने के लिए सालों तक संघर्ष किया है। बैगा जनजाति के 32 परिवारों का एक समूह अब बफर जोन के चिचरंगपुर गांव में रहता है, जहां एक गैर-लाभकारी संस्था उन्हें खेती और आजीविका के अन्य साधनों का प्रशिक्षण दे रही है। बैगा जनजाति की धीमरन बाई 70 साल की हैं। लेकिन उन्हें आज भी 48 साल पहले की बरसात की वो सुबह अच्छी तरह से याद है, जब वह अपने पति चरण सिंह बैगा और अपने नवजात शिशु के साथ ओमरई गांव के अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थीं। उनका गांव कान्हा राष्ट्रीय पार्क के अंदर स्थित था। इस नेशनल पार्क को 1973 में एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके बाद यहां रहने वाले आदिवासियों को यह जगह छोड़ने के लिए कहा गया। इस साल रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था। आदिवासी महिला ने बताया कि मेरी गोद में छोटा बच्चा था। बारिश का मौसम था और सरकार ने हमें हमारे घरों से निकाल दिया। सालों तक हम भूख से तड़पते रहे। अपना पेट भरने और अपने बच्चों को खिलाने के लिए जंगलों में भटकते रहे। वह सालों तक अपने पति के साथ मजदूरी करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकती रहीं थी। और आखिर में चिचरंगपुर आकर बस गईं। लेकिन यहां आकर भी उन्हें सुकुन नहीं मिला था। सालों तक बिना खेती और रोजगार के वे अपने दिन काटते रहे। बालाघाट जिले का चिचरंगपुर गांव मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। कान्हा में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन अर्थ फोकस कान्हा ने उनकी परेशानियों को समझा और उनकी सहायता के लिए आगे आया। आज उनका जीवन बदल गया है। यह संस्था 2019-20 से चिचरंगपुर में 32 बैगा परिवारों के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें खेती और रोजगार से जोड़ रही है। कहा जा सकता है कि बरसों की मशक्कत के बाद चिचरंगपुर गांव के बैगा दंपति और कुछ साथी आदिवासी परिवारों ने खेती और आजीविका के अन्य साधनों को अपनाकर एक नया जीवन शुरू किया है। गैर-लाभकारी आजीविका टीम के कार्यक्रम कॉर्डिनेटर किशन पुरी ने बताया कि हमने गांव के लोगों के पलायन को रोकने के मकसद के साथ बैगा परिवारों के साथ काम करना शुरू किया था। शिक्षा और स्थिर आजीविका मुख्य समस्याएं थीं और इसलिए हमने कान्हा के बफर जोन में स्थित गांवों के साथ काम करने के लिए जुट गए। विस्थापित बैगा परिवारों के साथ काम करना आसान नहीं था। ये लोग सालों से घोर गरीबी, भुखमरी और अभाव में जी रहे थे। बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। काम की तलाश में यहां से वहां घूमते अपने माता-पिता के साथ वे भी भटकते रहते थे।

बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ

काम की तलाश में इधर-उधर भटकने के बाद 1992 में धीमरन बाई और चरण सिंह अन्य 32 परिवारों के साथ चिचरंगपुर में आकर बस गए। चरण सिंह बैगा ने कहा कि यह पूरा जंगली इलाका था। हमने खाने के लिए कुछ उगाने के लिए जमीन को साफ किया। यह कठोर जमीन थी। एकदम बंजर। हर साल धान की सिर्फ एक फसल ही यहां हो पाती थी, वह भी पर्याप्त बारिश होने पर। उन्होंने कहा कि यह काफी मुश्किल था। कई आदिवासी परिवारों ने अपनी हिम्मत छोड़ दी थी।

जगली जानवर फसल कर देते थे बर्बाद

गोधर बैगा भी विस्थापित होने के बाद अपने परिवार के साथ चिचरंगपुरा आ गए थे। अन्य बैगा लोगों के साथ हमने कुछ जंगलों को साफ किया और यहां आकर बस गए। विस्थापित आदिवासियों ने बंजर जमीन पर बाजरा उगाने की कोशिश की थी। लेकिन जंगली जानवर फसल को बर्बाद कर देते थे। सो, हमें काम के लिए दूसरे गांवों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोधर चिचरंगपुरा गांव में खेती कर रहे हैं। मैं अब सब्जियों के अलावा अपने खेत में मटर और छोले भी उगा रहा हूं।

योजनाओं की दे रहे जानकारी

अर्थ फोकस कार्यक्रम कोर्डिनेटर पुरी ने कहा कि हम उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर, अच्छी किस्म के बीज मुहैया कराते हैं। उनके खेतों की सिंचाई के लिए पंप की व्यवस्था करके खेती की तरफ उन्हें फिर से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें खाद और कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। गैर-लाभकारी संगठन आदिवासियों को कागजी कार्रवाई जैसे फॉर्म भरना,योजनाओं के लिए आवेदन करना आदि में मदद करता रहा है। उन्हें नई सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

गांव वालों की मदद कर रहा संगठन

संगठन और भी कई तरीकों से गांव वालों की मदद कर रहा है। यह उनके लिए बागवानी विभाग से पौधे लाता है, कृषि विज्ञान केंद्रों से बीज खरीदता है और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों जैसे गाय के गोबर आदि से खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण देता है। अर्थ फोकस के संस्थापक विपुल गुप्ता ने कहा कि हम उस पर्यावरण को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आदिवासी विस्थापित होने के बाद खो चुके हैं। हम आदिवासियों को उनकी बंजर भूमि में पेड़ और झाड़ियां लगाने में मदद कर रहे हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने वाले चिचरंगपुरा में आदिवासियों को वन विभाग से खेती करने की अनुमति मिली हुई है।

मनरेगा से मिली मदद

एक अनूठी पहल में बागवानी विभाग, पंचायत विभाग और गैर-लाभकारी अर्थ फोकस कान्हा ने मिलकर आदिवासी किसानों को मनरेगा के तहत उनके खुद के खेतों पर काम करने में मदद की है, ताकि वह एक स्थिर आमदनी पा सकें। चिचरंगपुरा में 12 परिवारों के हर दो सदस्य जुलाई 2022 से मनरेगा योजना का लाभ उठा हो रहे हैं। चरण सिंह ने कहा कि हमें मनरेगा के तहत 15 दिनों के लिए काम मिलता है, इससे महीने में 2,800 रुपए की कमाई हो जाती हैं। एक महीने पहले चिचरंगपुरा के आदिवासी किसानों ने बागवानी विभाग, कृषि विभाग और राष्ट्रीय बांस मिशन के साथ मिलकर अपनी आवंटित जमीन के 30 फीसदी हिस्से पर लगभग एक हजार बांस के पौधे लगाए थे। इससे उनकी खेतों को सुरक्षा और एक तरह की प्राकृतिक बाड़ मिल गई। इसके अलावा यह राजस्व का एक स्रोत भी बन गया।

मप्र ने केंद्र से मांगे 2,500 करोड़

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बताया कि पुराने राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 45 गांव थे। पिछले कुछ सालों में 32 वन गांव को उनकी इच्छा से मुख्य क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। इससे जंगली जानवरों भी रहने के लिए अतिरिक्त जगह मिल गई। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बाघ अभयारण्यों को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि मौजूदा 89 गांवों को पांच बाघ अभयारण्यों के कोर और बफर जोन से स्थानांतरित किया जा सके।

पिछड़ों का सशक्त बनाना लक्ष्य

विपुल गुप्ता ने कहा कि हमारा इरादा उन्हें कुछ भी दान में देना जैसा नहीं है। बल्कि समुदायों को खुद के लिए लड़ने और आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने और ऐसा करना जारी रखने के लिए सशक्त बनाना है। कान्हा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह का कहना है कि आदिवासियों के विस्थापित होने के बाद मुआवजे के तौर पर आदिवासियों को रहने और खेती करने के लिए एक से चार एकड़ जमीन दी गई है।

2009 में मिला मुआवजा

चरण सिंह बैगा ने बताया कि सालों तक भटकने के बाद उन्हें 2009 में ये मुआवजा मिल पाया था। 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत, उन्हें चिचरंगपुरा में 1.565 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिला। कान्हा के मुख्य क्षेत्र में मेरे पास 80 एकड़ जमीन थी। हमारे पास अपना तालाब था जहां से हम सिंचाई के लिए पानी भरते थे। यहां इसी तरह हर आदिवासी परिवारों को कुछ न कुछ जमीन दी गई है।

आज भी कई विस्थापित बेघर

आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए काम करने वाली बालाघाट स्थित एकता परिषद के एस भोंडे के अनुसार- 1973-74 में जब आदिवासी निवासियों को विस्थापित किया गया था, तो उनमें से प्रत्येक को अस्थायी रूप से रहने के लिए सिर्फ एक एकड़ जमीन दी गई थी। आज भी पांच या छह विस्थापित गांवों के निवासी बेघर हैं।

सुखद भविष्य का प्रयास है प्राकृतिक खेती

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिण्ड) म.प्र.

प्राकृतिक खेती भविष्य की कृषि है। आने वाला समय प्राकृतिक कृषि का ही है। यदि हमको स्वयं तथा अपने समाज को रोग मुक्त रखना है तो हमें प्राकृतिक खेती अपनानी ही होगी। प्राकृतिक कृषि कम लागत और मात्र एक भारतीय देसी गाय के साथ की जा सकती है। आज समय की जरुरत है कि प्राकृतिक कृषि के प्रति किसानों और आम जनमानस में जागरूकता पैदा की जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को उन्मुख हों और इसे अपनाने के लिए आगे आएं।

प्राकृतिक खेती में देशी गाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान एक गाय के साथ 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती आसानी से कर सकते हैं। देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक जमीन के लिए उपयोगी बैक्ट्रिया पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ाने से लेकर जमीन की जल धारण क्षमता तक को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जमीन में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले बैक्टीरिया जमीन को भुरभुरा बनाने से लेकर उसके अंदर वायु स्पेस को बढ़ावा देते हैं। जिससे जमीन धीरे-धीरे उपजाऊ होकर प्राकृतिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत होती है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसके चलते प्राकृतिक खेती में पैदा होने वाले उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं बल्कि इनसे कई प्रकार के प्राण घातक रोगों से बचा जा सकता है।

आज हमारे देश के साथ पूरे विश्व में दो तरह की कृषि पद्धति अपनाई जा रही है जिसमें रासायनिक खेती और जैविक खेती प्रमुख है। लेकिन भारत में एक नई पहल के तहत आज प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। हालांकि भारत के लिए प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है, हमारे देश में सदियों से किसान प्राकृतिक खेती पर निर्भर रहे हैं और इसे करते आए हैं। लेकिन हरित क्रांति के दौर के बाद जिस प्रकार से खेती और किसानी में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है उसके चलते धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती विलुप्त होती चली गई। जिसे आज पुनः एक बार प्रचलन में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्राकृतिक कृषि भविष्य की कृषि है। इसको बढ़ावा देकर तथा किसानों द्वारा इसे अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों को रोग और बीमारियों से मुक्ति के साथ ही एक अच्छी जमीन अपनी संतति के लिए छोड़कर जा पाएंगे। जिस प्रकार से विगत कुछ दशकों में खेतिहर जमीन के अंदर रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। उसे देखते हुए एक तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हुई है वही प्राणघातक बीमारियों के प्रकोप से कैंसर जैसी महामारी का प्रभाव आम लोगों के बीच में बड़ा है। आज लोगों के पास पैसा है दौलत है, परंतु अच्छा भोजन जहरमुक्त खाने-पीने के कृषि उत्पाद मिलना मुश्किल हो रहा है। किसान धीरे-धीरे प्राकृतिक कृषि की ओर उन्मुख होते हैं तो आने वाले समय में आम जनमानस को जहर मुक्त कृषि उत्पाद आसानी से सुलभ हो सकेंगे। इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और बीमारियों पर होने वाला खर्चा कम होने के साथ ही वह अपनी प्राण रक्षा भी कर सकेंगे। इसलिए आज नहीं तो कल हमें प्राकृतिक खेती की ओर सोचना ही नहीं, बल्कि उसकी और आगे बढ़ना ही होगा। प्राकृतिक कृषि जहां मृदा और मानव के अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है वही प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसान अपनी खेती में बढ़ने वाली लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक कृषि गौ आधारित अर्थात देशी गाय आधारित कृषि है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक कृषि के माध्यम से हम गाय और खासकर भारतीय गाय की रक्षा कर पाएंगे। आज गांव कस्बों से लेकर शहरों, महानगरों यहां तक कि सड़कों और हाईवे तक पर आवारा देसी घुमंतू गायों के झुंड के झुंड देखे जा सकते हैं। यह कहना थोड़ा कड़वा है, परंतु सत्य है कि यह जो आज आवारा गाय हैं वह हमारे किसानों द्वारा छोड़ी हुई ऐसी गाय हैं, जो दुग्ध उत्पादन नहीं करती

हैं अथवा बांझपन की शिकार है। अनउत्पादक होने के कारण ही किसानों ने इन्हें आवारा छोड़ दिया है। आज हमारे देश के गांव कस्बों से लेकर शहरों तक में लाखों करोड़ भारतीय गोवंश दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं।

प्राकृतिक कृषि में आवारा घुमंतू देसी गांव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बताया जाता है कि आवारा घुमंतू देसी गाय के गोबर और मूत्र में पालतू देसी गाय से भी ज्यादा खेती में काम आने वाले कीटाणु पाए जाते हैं। ऐसे किसान जिनके पास आज देसी गाय नहीं है वह भी आवारा घूमने वाली देसी गाय को पकड़कर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इससे जहाँ आवारा देसी गाय को नया जीवनदान मिलेगा उन्हें भरपेट भोजन मिल सकेगा वहीं किसान की आमदनी में इजाफा होने के साथ ही उनके खेतों की मिट्टी की दशा और दिशा में सुधार होगा। किसानों का इस प्रकार का कदम देसी गाय की रक्षा के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। इसलिए किसानों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने के साथ ही इसे जितनी जल्दी हो सकता है अपनाने की जरूरत है।

प्राकृतिक कृषि के तहत तैयार किए जाने वाले उत्पादों में जीवामृत, घनजीवामृत, वीजामृत आदि को तैयार करने में देशी गाय के गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नेमपेस्ट, दशपर्णी अर्क, सप्तधान्य आदि आज को तैयार करने में देसी गाय का गोबर और गोमूत्र, गुड़, बेसन के अलावा घर में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अनाज और दानों की आवश्यकता पड़ती है।

फसलों और पेड़ पौधों को विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों से बचाने के लिए तैयार होने वाले उत्पादों के लिए भी विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियां, तंबाकू, हरी मिर्च, पुरानी खट्टी छाछ, लहसुन आदि के अलावा देसी गाय के गोमूत्र की विशेष महत्ता है। प्राकृतिक खेती में किसानों की फसलों पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा होने वाले कृषि उत्पाद रोग और बीमारियों से मुक्त होते हैं जिससे हम अपने आप को विभिन्न बीमारियों और रोगों से बचा सकते हैं। आज कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी इन कीटनाशकों और रासायनिक खेती की वजह से ही पैदा हो रही है। इसलिए समय की मांग है कि किसान प्राकृतिक खेती की और आगे आए और इसे अपनाएं। किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्से से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले सीजन से प्राकृतिक खेती से प्राप्त परिणामों को देखकर आगे इसे और बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक कृषि से सुखद और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसे देखकर धीरे-धीरे संपूर्ण भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। प्राकृतिक कृषि जहरमुक्त खेती की ओर एक सुखद भविष्य का प्रयास है। प्राकृतिक कृषि फसलों, फल-फूल, बागवानी, सब्जी, मसाला, दलहनी, तिलहनी, खांद्यान फसलों से लेकर चारा फसलों में प्राकृतिक खेती के उत्पादों का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है।

आज कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली मिशन मोड में प्राकृतिक कृषि के प्रति किसानों को जागरूक करने और प्राकृतिक कृषि को अपनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों,कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों एवं राज्य सरकारों के कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों के माध्यम से वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है।

आज जरूरत इस बात की है कि किसान प्राकृतिक कृषि से होने वाले लाभ बारे में भली प्रकार से समझे जाने और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्राकृतिक खेती की ओर आगे आएं। आज किसानों को सोचना है कि वह प्राकृतिक खेती से किस प्रकार से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आज प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में अलख जगाने का काम हो रहा है अभी भी किसान नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और इस देर की भरपाई करना आने वाली पीढ़ियों के लिए दुष्कर होगा। इसलिए जागो सोचो और प्राकृतिक खेती को अपनाने की ओर हाथ आगे बढ़ाओ। क्योंकि आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि से ही हमारा और आपका जीवन बचने वाला है।

रबी फसलों के लिए चिंता कारण, पश्चिमी विक्षेभ का नदारद रहना

उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बन्स का नदारद रहना रबी फसलों के लिए चिंता को बढ़ा रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और नमी की भी कमी है। जोकि सर्दियों में गेहूं की फसल के लिए बहुत मायने रखती है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बन्स भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में आने वाला तूफान है, जो नमी लाकर अचानक बारिश और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देते हैं। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली 'वेस्टरली जेट धाराओं' के साथ यात्रा करते हैं।

यदि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 13 दिसंबर तक के लिए जारी आंकड़ों को देखें तो उत्तर-पश्चिमी भारतीय राज्यों में बारिश की कमी है, केवल पंजाब में ही मौसमी बारिश (1 अक्टूबर से 13 दिसंबर) में औसत से 33 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। वहीं बाकी राज्यों में या तो सामान्य, या सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है।

देखा जाए तो मौसम की सक्रिय कई प्रणालियों के चलते अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में इस क्षेत्र में लगातार बारिश हुई थी, जिसने इस विरोधाभास का जन्म दिया। वहीं भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में जारी ला नीना की घटना और गर्म होते आर्कटिक क्षेत्र के संभावित प्रभाव की भी इसमें भूमिका हो सकती है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद हुई बारिश पहले ही अधिकांश क्षेत्रों से हट चुकी है। उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश हुई है। कुछ राज्यों में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। इससे संभवतः नमी का स्तर काफी कम हो गया है, जिससे रबी फसलों की वृद्धि प्रभावित हुई है। ऐसे में असामान्य बारिश क्षेत्र की मौसमी वर्षा में बदल गई है।

यह विषमता सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 1 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच हुई मौसमी बारिश 344 फीसदी ज्यादा थी। गौरतलब है कि राज्य में इस अवधि के दौरान 145.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। देखा जाए तो 1 से 16 अक्टूबर के बीच यूपी में कुल 145.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मतलब की 16 अक्टूबर से 13 दिसंबर, लगभग दो महीनों में राज्य में केवल 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

देखा जाए तो अक्टूबर की शुरूवात में हुई भारी बारिश के लिए जिम्मेवार मौसम प्रणालियों में एक पश्चिमी विक्षोभ भी था। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर के बाद से वर्षा में आई कमी का मुख्य कारण नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ में आई कमी और दिसंबर में उसका पूरी तरह गायब होना जिम्मेवार है।

नवंबर में लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ आए थे। पहला उत्तर पश्चिम भारत में 5 से 8 नवंबर, दूसरा 9 से 10 नवंबर और तीसरा 13 से 19 नवंबर तक प्रभावित करता रहा। आईएमडी के आंकड़ों के किए विश्लेषण से पता चला है कि तीन पश्चिमी विक्षोभों के चलते नवंबर के पहले दो हफ्तों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलग-अलग हिस्सों में कुछ बारिश दर्ज की गई थी।

नवंबर 2017 में क्वार्टरली जर्नल ऑफ द रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक रिसर्च से पता चला है कि आमतौर पर दिसंबर में 3 से 5 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। दिसंबर 2019 में भी उत्तर पश्चिमी भारत में इसी तरह की कमी दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों ने इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ का दक्षिण के मैदानी इलाकों को प्रभावित न करने को जिम्मेवार बताया था। वहीं इस बार वे पूरी तरह नदारद रहे हैं।

इस बारे में मैरीलैंड विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के विजिटिंग प्रोफेसर रघु मुर्तुगुड्डे ने बताया कि, चक्रवात मैंडूस के बावजूद, पूर्वोत्तर मानसून ने अंदरूनी इलाकों में बारिश की है। वहीं भारत के पूर्वी तट पर बारिश की कमी है।

उन्होंने बताया कि यह ला नीना प्रेशर पैटर्न है। हवाएं उत्तर से चलेंगी, जो पश्चिमी विक्षोभ के लिए प्रतिकूल है। मुर्तुगुड्डे का कहना है कि, ला नीना के बावजूद, चक्रवात की गतिविधि कमजोर रही है। इससे ठंडी हवाएं प्रायद्वीप में और नीचे जाएंगी, ऐसे में उत्तर पश्चिम भारत सामान्य से अधिक गर्म हो सकता है। उनका कहना है कि यह कृषि और भूजल के लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन पश्चिमी

समय का साक्षी ताड़ का पेड़

जयंत सिंह तोमर
लेखक एवं प्राध्यापक
आइटीएम यूनिवर्सिटी

पंक्तिबद्ध ताड़ के पेड़ों को देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि ये एक सीध में अपने आप ही उगते हैं या बाकायदा लगाये जाते हैं। रामायण का सुग्रीव और राम की पहली भेंट का प्रसंग याद आता है । सुग्रीव को किसी ने बताया है कि ताड़ के सात पेड़ एक तीर से जो गिरा दे वही बाली को हरा सकता है। सुग्रीव के कहने पर राम जब ऐसा कर दिखाते हैं तो सुग्रीव को भरोसा होता है।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आश्रम में एक घर का नाम ही है तालध्वज। पुआल से छाये एक कच्चे घर के बीच से एक ताड़ का पेड़ आसमान की ओर निकल गया है। सौ साल पहले भी तालध्वज घर अस्तित्व में था। इससे यही पता चलता है कि ताड़ का पेड़ भी सौ साल से ज्यादा ही पुराना है । गुरुदेव ने तालगाछ शीर्षक एक बहुत सुन्दर कविता भी लिखी है जो तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाई जाती थी। कविता का मर्म यह है कि सुबह होते ही ताड़ का पेड़ आसमान में उडने को लालायित होता है, डैने जैसे पत्तों के सहारे समूचे नभ की परिक्रमा करता है, लेकिन शाम ढलते ढलते उसे धरती माता की याद आती है तो वापस लौट आता है। बाल मनोविज्ञान की एक प्रतिनिधि कविता है यह। शुंगकालीन ताड़ स्तम्भ शीर्ष ग्वालियर के गूजरी महल संग्रहालय की शोभा हैं। सम्राट अशोक के समय में स्तम्भ के शीर्ष पर सिंह बनाये जाते थे। लेकिन दो हजार साल पहले शुंग व नागवंशी शासकों ने ताड़ स्तम्भ बनवाये। ताड़ के पत्तों को

हूबहू ऐसा बनाया है जैसे कलाकार बलवीर सिंह कट्ट ने आकर उन्हें तराशा हो। ताड़ के फल बरसात में पकते हैं। आप नीचे खड़े हों और कब धप्प से आकर गिर जाए कुछ पता नहीं होता। फल से बड़ी अच्छी सुगंध आती है। इसके रस से पूए बनते हैं। छोटे नालों को पार करने के लिए ताड़ के तने पुल का भी काम करते हैं। कैसे भी आंधी तूफान आये ताड़ के पेड़ अविचल भाव से समय के साक्षी बनकर खड़े रहते हैं।

पंचायत चुनाव की गतिविधियों का मुनादी कर करें प्रचार-प्रसार

भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत आम/उप निर्वाचन के

संबंध में मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं, सुविधा केन्द्रों की स्थापना, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने और मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में मुनादी करवा कर भी दी जाए। प्रचार-प्रसार के दौरान यह भी बताया जाए कि पंचायतों के निर्वाचन में पंच पद के निर्वाचन मतपत्रों पर मुहर लगा कर, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे।

किसानों के खेतों पहुंच कर लिया बिजली व्यवस्था का जायजा

» बिजली कम्पनी के एमडी ने किया दूधिया क्षेत्र का निरीक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने इंदौर ग्रामीण वृत्त के अधीन दूधिया वितरण केंद्र क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने खेतों के पास पहुंच कर सिंचाई के लिए दी जा रही बिजली व्यवस्था एवं केपेसिटर बैंक की जानकारी ली। केपेसिटर बैंक को कंपनी के लिए अच्छी पहल बताया। तोमर ने कहा कि बिजली का गुणवत्तापूर्ण वितरण, समय पर लक्ष्य के मुताबिक राजस्व संग्रहण, उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर और बढ़ाने के लिए गंभीरता से कार्य हो। प्रबंध निदेशक ने इंदौर ग्रामीण संभाग के नेमावर रोड औद्योगिक इलाके की आपूर्ति व्यवस्था संबंधी जानकारी भी ली और उद्योगों के संचालकों की नियमानुसार मदद करने को कहा। मुख्य अभियंता पुनीत दुबे, अधीक्षण अभियंता डॉ. डीएन शर्मा, कार्यपालन अभियंता अभिषेक रंजन आदि मौजूद थे।

मत्स्य-पालकों के हित में मध्यप्रदेश के बढ़ते कदम

» केंद्र से मिला मप्र को पुरस्कार, सीएम ने कैबिनेट बैठक के पहले की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण से प्रदेश की कुछ उपलब्धियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को विश्व मत्स्य दिवस 22

नवंबर को पुरस्कृत किया गया है। मत्स्य महासंघ को श्रेष्ठ महासंघ का दर्जा मिला है। प्रदेश में मत्स्य-पालन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गत वर्ष भी प्रदेश को पुरस्कृत किया गया था। मत्स्य-पालन के क्षेत्र में बालाघाट जिला देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिले के रूप में चयनित हुआ था। मुख्यमंत्री ने मत्स्य-पालन विभाग की पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

कम उम्र में सामने आ रही हैं गंभीर बीमारियां

मिट्टी की सेहत खराब होने का असर मानव शरीर पर पड़ रहा

- मिट्टी में रसायनों का अंधाधुंध उपयोग बढ़ने से खत्म हो रहा आर्गेनिक कार्बन

भोपाल। मिट्टी में रसायनों का अंधाधुंध उपयोग बढ़ने से आर्गेनिक कार्बन खत्म हो रहा है। इससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। इसका असर मानव शरीर पर भी हो रहा है। ऐसी मिट्टी में उपजी सब्जियों, अनाज, दलहनों में भी रसायनों का असर आ रहा है। इनका खाने में उपयोग होने से शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। कम उम्र में गंभीर बीमारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान की जरूरत है। रसायनों के उपयोग से मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम हुई है और मिट्टी बीमार हो रही है। ऐसे में गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ानी होगी। मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. एसके बांगर का कहना है कि मिट्टी में मित्र कीट बढ़ने से ही मिट्टी की सेहत सुधरेगी। मिट्टी सेहतमंद होगी तो उपज भी स्वास्थ्यवर्धक होगी। किसानों को मिट्टी व पानी का परीक्षण करवाना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों का सीमित निर्धारण होगा। जागरूक होने की जरूरत है। स्वयं व लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को खेती करनी चाहिए।

20 साल से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत

विशेषज्ञों के अनुसार 20 साल से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। 70 फीसदी मिट्टी के सैम्पलों में आर्गेनिक कार्बन कम आ रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग बढ़ा है। मिट्टी परीक्षण होने से रसायनों का उपयोग 50 फीसदी तक कम हो जाएगा। मिट्टी में जिन तत्वों की कमी होगी, किसान सिर्फ उन्हीं उर्वरकों को डालेगा। सभी किसानों को मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। ग्वालियर कृषि विवि के मृदा विज्ञान के विभाग अध्यक्ष एसके त्रिवेदी का कहना है कि मिट्टी की सेहत को लेकर युवा किसानों को जागरूक होना होगा। मिट्टी की सेहत से पूरे समाज की सेहत जुड़ी है। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ना होगा। मिट्टी में जैव-विविधता बढ़ानी होगी। इसके लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। आज कृषि वैज्ञानिकों की ज्यादा सलाह नहीं ली जा रही है। इससे मिट्टी में रसायनों का बिना मानक व गाइडलाइन के ज्यादा उपयोग हो रहा है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी कम हुई है।

आने वाला समय प्राकृतिक कृषि का

भिंड। जागत गांव हमार

प्राकृतिक खेती भविष्य की कृषि है आने वाला समय प्राकृतिक कृषि का ही है। यदि हमें और हमें अपने समाज को रोग मुक्त रखना हैं तो हमें प्राकृतिक खेती अपनानी ही होगी। प्राकृतिक कृषि कम लागत और मात्र एक भारतीय देसी गाय के साथ की जा सकती है। यह विचार कृषि विज्ञान केंद्र, लहार के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एस पी सिंह द्वारा गोहद ब्लॉक में प्राकृतिक खेती जागरूकता कायक्रम एवं प्रशिक्षण के दौरान किसानों के बीच व्यक्त किए गए। किसानों को संबोधित करते हुए डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती में देशी गाय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान एक गाय के साथ 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती आसानी से कर सकते हैं। देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक जमीन के लिए उपयोगी बैक्टिरिया पाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि के तहत तैयार किए जाने वाले उत्पादों में जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत आदि को तैयार करने में देशी गाय के गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नेमपेस्ट, दशपर्णी अर्क, सप्तधान्य आदि आज को तैयार करने में देसी गाय का गोबर और गोमूत्र, गुड़, बेसन के अलावा घर में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अनाज और दानों की आवश्यकता पड़ती है।

फसलों और पेड़ पौधों को विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों से बचाने के लिए तैयार होने वाले उत्पादों के लिए भी विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियां, तंबाकू, हरी मिर्च, पुरानी खट्टी छाछ, लहसुन आदि के अलावा देसी गाय के गोमूत्र की विशेष महत्ता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में किसानों की फसलों पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा होने वाले कृषि उत्पाद रोग और बीमारियों से मुक्त होते हैं, जिससे हम अपने आप को विभिन्न बीमारियों और रोगों से बचा सकते हैं। आज कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी इन कीटनाशकों और रासायनिक खेती की वजह से ही पैदा हो रही है। इसलिए समय की मांग है कि किसान प्राकृतिक खेती की और आगे आए और इसे अपनाएं। डॉ. सिंह ने किसानों से अपील की कि वह अपनी जमीन के कुछ हिस्से से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और इसके परिणाम देखकर आगे बढ़े। प्राकृतिक कृषि जहरमुक्त खेती की ओर एक सुखद भविष्य का प्रयास है।

केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. करणवीर सिंह द्वारा किसानों को सब्जी फसलों में प्राकृतिक खेती की उत्पादों के प्रयोग करने की सलाह दी तथा इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के बारे में किसानों को बताया। केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ बीपीएस रघुवंशी द्वारा इस अवसर पर जीवामृत, घन जीवामृत बनाने के बारे में किसानों को अवगत कराया गया। गोहद ब्लॉक की बीटीएम श्रीमती मोनिका भास्कर द्वारा प्राकृतिक कृषि के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत के फसलों में प्रयोग के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर किसान नारायण बाथम के यहां कृषि विज्ञान केंद्र, लहार द्वारा स्थापित प्राकृतिक कृषि इकाई के माध्यम से जीवामृत बनाकर किसानों को दिखाया गया।

पशु स्वास्थ्य शिविर में जांच एवं निःशुल्क इलाज

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा ग्राम नन्नी टेहरी विकासखंड टीकमगढ़ में जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार परियोजना अंतर्गत पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. बी.एस. किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आर.के. प्रजापति वैज्ञानिक डॉ.एस. के. जाटव, जयपाल छिगारहा एवं पशुपालन विभाग से डॉ. पाठक (एवीएफओ) और ग्राम पंचायत के सरपंच व पशुपालकों ने भाग लेकर गाय, भैंस व बकरियों की जांच एवं निशुल्क इलाज किया गया । वैज्ञानिकों द्वारा पशुपालन पशुओं में होने वाली बीमारियों एवं उनके प्रबंधन के बारे में बताया गया । पशु हमारी खेती का मुख्य आधार है पशुपालकों को पशुओं से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्नत नस्ल के पशु पाले और पशुओं की नस्ल सुधार के लिए पशुपालन विभाग से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कराया । जिससे पशुओं की स्थानीय नस्लों में सुधार होने से उनमें दूध देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी जिससे किसान की आय में भी वृद्धि होगी । पशु के रहने की जगह (सार) साफ-सुथरी होना चाहिए जिससे पशुओं को बैठने में आराम होगा और मच्छर मक्खियाँ भी पैदा नहीं होंगी । पशुपालकों को वर्ष भर में 2 बार नियमित रूप से बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण अवश्य लगवाना चाहिए । पशु चिकित्सक डॉ. पाठक द्वारा गाय, भैंस, बकरी व उनके छोटे बछड़े/पड़िया आदि की जांच कर इलाज भी किया गया उन्हें निशुल्क दवाएं भी वितरण की गई । साथ ही किसानो को नेपियर हाइब्रिड बाजरा भी वितरित किया गया । नेपियर हाइब्रिड बाजरा बहुवर्षीय चारा है इस चारे से वर्षभर हरा चारा उपलब्ध होता जिससे किसानो को बार बार हरा चारा नहीं लगाना प?ता है नेपियर हाइब्रिड बाजरा एक गुणवत्ता पूर्ण चारा होता है जिससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता में ब्रद्धि होती है ।

स्वयं सिद्धा स्वावलंबन भारत ट्रेड फेयर का हुआ शुभारंभ

गांवों के आत्मनिर्भर बनने से देश बनेगा आत्म-निर्भर

भोपाल। जागत गांव हमार

खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्राचीन समय में देश के गाँवों की सुदृढ़ और समृद्ध अर्थ-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि गांवों को आत्म-निर्भर बनाने से ही आत्म-निर्भर भारत बनेगा और हम स्वावलंबी बनेंगे। मंत्री कटनी के दिव्यांचल गार्डन बरगवां मे लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम, उद्यम विभाग और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में स्वयंसिद्धा स्वावलंबन भारत ट्रेड फेयर के शुभारंभ समारोह में कही। मंत्री ने कहा कि कटनी प्रदेश का हृदय स्थल है और यहां उद्योग स्थापना के साथ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। उन्होंने कहा कि इस संपदा के वैज्ञानिक रूप से दोहन के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यहां स्टोन का कार्य होता था। अब मार्बल, माइन्स, खेती, कपड़ा व्यवसाय, मिनरल्स की उपलब्धता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देकर लोगों को आत्म-निर्भर बनाने की बात कही। गांव एवं शहर के लोगों को उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी एवं आत्म-निर्भर बनने की जरूरत बताते हुए सिंह ने कहा कि लधु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से ही अर्थ-व्यवस्था बेहतर होगी।

युवा स्व-रोजगार लगाएं- मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों की भी जानकारी दी। अकुशल होने की वजह से उद्योग धंधों मे स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। उन्होंने ऐसे युवाओं के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि युवा आगे आएं, स्व-रोजगार लगाएं और दूसरों को भी रोजगार दें।

यह भी रहे मौजूद

विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक, कटनी मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता, महामंत्री अरूण सोनी ने भी समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के जाप और दीप प्रज्वलन कर किया गया।

स्टालों का अवलोकन

खनिज सांधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने तीन दिवसीय स्वयंसिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर में प्रदर्शन स्टालों का निरीक्षण किया।

केवल एक देशी गाय की सहायता से कर सकते हैं प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती पर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ में विगत दिवस प्राकृतिक खेती पर डॉ. बी.एस. किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. आर.के. प्रजापति, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. एस.के. जाटव, डॉ. आई.डी. सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों एवं कृषि स्नातक छात्रों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। यह पद्धति प्रकृति, विज्ञान, आध्यात्मिक एवं अहिंसा पर आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रासायनिक खाद, जैविक एवं जहरीले कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं शाकनाशी रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं होता। आप केवल एक देशी गाय की सहायता से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इस पद्धति से शस्य उत्पादन, जहर मुक्त, उच्च गुणवत्ता युक्त, पोष्टिक एवं स्वादिष्ट होगा। इन गुणों व विशेषताओं के कारण उपभोक्ताओं द्वारा इनकी माँग अधिक होने से मूल्य भी अच्छा मिलेगा। रासायनिक खेती से मानव, पशु, पक्षी, भूमि, जल एवं पर्यावरण को काफी हानि हो रही है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्रत्येक किसान को कम लागत वाली प्राकृतिक खेती को अपनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती के प्रमुख घटक बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत एवं वापसा और

वृक्षाकार प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता है। बीजामृत घोल तैयार कर बीजों का उपचार (संशोधन) करना बहुत जरूरी है। बीजामृत द्वारा शुद्ध बीज जल्दी एवं अच्छी मात्रा में अंकुरित होते हैं और जड़ें तेजी से बढ़ती हैं साथ ही बीज एवं भूमि द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ रूकती हैं और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। घन जीवामृत अंतर्गत 100 कि.ग्रा. देशी गाय का गोबर, 1 कि.ग्रा. गुड़, 2 कि.ग्रा. दलहन का आटा (चना, उड़द, मूँग, अरहर), एक मुट्ठी पीपल / बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और थोड़ा सा गोमूत्र, आदि पदार्थों को अच्छी तरह से मिलाकर गूँथ लें ताकि उसका हलुवा, लड्डू जैसा गाढ़ा बन जाये। उसे 2 दिन तक बोरे से ढककर रखें और थोड़ा पानी छिड़क दें। इस गीले घन जीवामृत को आप छाया या हल्की धूप में अच्छी तरह से फैलाकर सुखा लें। सूखने के बाद इसको लकड़ी से पीटकर बारीक करें और बोरों में भरकर छाया में भण्डारण करें। घन जीवामृत को आप सुखाकर 6 महीने तक रख सकते हैं। फसल की बुवाई के समय प्रति एकड़ 100 कि.ग्रा. छना हुआ बीज में मिलाकर बुवाई करें। जीवामृत एक एकड़ जमीन के लिए देशी गाय का गोबर 10 कि.ग्रा., देशी गाय का मूत्र 8-10 ली., गु? 1-2 कि.ग्रा., बेसन 1-2 कि.ग्रा., पानी 180 ली. और पेड़ के नीचे की 1 कि.ग्रा. मिट्टी, आदि सामग्रियों को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डण्डे से हिलाकर घोलना चाहिए।

-राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा

सरकार शहरों जैसी सुविधाएं अब गांवों तक पहुंचा रहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार ने शहर जैसी बुनियादी सुविधाओं को गाँवों तक पहुँचाने का काम किया है। गांवों में जल जीवन मिशन से हर घर में नल से पानी, उत्कृष्ट सड़कें, केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल, हर गांव के नजदीक स्वास्थ्य केन्द्र और बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का काम सरकार कर रही है। राज्य मंत्री कुशवाह ग्वालियर के साडा क्षेत्र के ग्राम सौजना में एक करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों के भूमि-पूजन एवं लोकर्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कुशवाह ने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर साडा क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 60 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जल्द ही यह जल परियोजना मूर्त रूप लेगी और निवासियों को फिल्टर किया हुआ पानी नल से उपलब्ध होगा।

उप स्वास्थ्य केन्द्र की आधार शिला रखी

राज्य मंत्री कुशवाह ने ग्राम सौजना में 71 लाख 16 हजार रुपए की लागत से बनने जा रहे उप स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला रखी। साथ ही 16 लाख रुपए लागत के रपटा सह रिंगबंड का भूमि-पूजन किया। ग्राम झाले का पुरा में 5 लाख 70 हजार लागत से हुए विद्युतीकरण कार्य और ग्राम परपटे का पुरा में 7 लाख 66 हजार रुपए की लागत से बनाई गई सीसी रोड का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में सौजना सहित अन्य समीपवर्ती गांवों के निवासी मौजूद थे।

कृषि मंत्री नए ट्रांसपोर्ट नगर का स्थल किया निरीक्षण

छिंदवाड़ा जिले के विकास का तेजी से घूम रहा पहिया

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। जन-कल्याण की योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। कृषि मंत्री पटेल छिंदवाड़ा में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर जन-कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतरीन कार्य करने वालों को पुरस्कृत करती है और अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकती। राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

छिंदवाड़ा में बनेगा नवीन ट्रांसपोर्ट नगर

कृषि मंत्री पटेल ने छिंदवाड़ा में बनने वाले नवीन ट्रांसपोर्ट नगर का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 13 करोड़ रुपए की लागत से नवीन ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने छिंदवाड़ा से गुरैया रोड पर बन रही पुलिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को शीघ्रता से तत्परतापूर्वक करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में जनता को लाभान्वित करने में छिंदवाड़ा जिला नम्बर-1 पर है। मंत्री ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा की जन-भागीदारी समिति के नव-निर्वाचित अध्यक्ष भारत घई को बधाई दीं।

कार्यालय नगर परिषद मनगवॉ जिला रीवा (म.प्र.)-

क्रमांक/1419/ई-निविदा/न.प./2022 मनगवां दिनांक 13-12-2022

प्रथम निविदा (सेक्सन-1)

ई निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद मनगवॉ द्वारा निकाय के विभिन्न वार्डों में बोरवेल खनन एवं हैण्डपम्प स्थापन कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्ते एवं जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in ÂÚU Urban Administration Development Department से एवं कार्यालय नगर परिषद मनगवां से प्राप्त की जा सकती है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा। विवरण निम्नानुसार है।

क्र	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा फार्म का मूल्य	कार्य की अवधि
	2022-UUAD-237565-1	नगर परिषद् मनगवाँ के विभिन्न वार्डों में खनन एवं हैण्डपम्प स्थापन का कार्य	5067403.00	38006.00	10000.00	03 माह

उक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र उपरोक्तानुसार दिये गये दिनांक 13.12.2022 सायं 05 :30 से दिनांक 12.01.2023 तक सायं 05 :30 तक वेबसाईट पर लागू प्रोसेसिंग शुल्क के ऑन लाईन भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेगें।

(श्रीमती बुटला बंसल)
अध्यक्ष
नगर परिषद मनगवाँ जिला रीवा (म.प्र.)

(सुरेश कुमार सोनवानी)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मनगवाँ जिला रीवा (म.प्र.)

नीरज भदौरिया
मीडिया प्रभारी भाजपा

मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

डेढ़ हजार लोगों के जीवन में केंद्रीय मंत्री तोमर ने जलाई नेत्र ज्योति

मुरैना। जागत गांव हमार

लोगों ने जिस काम के लिए सांसद के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को चुना, उस काम को तोमर ने आशा से अधिक जिम्मेदारी के साथ निभाया है। केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर सारे देश के किसानों की चिंता करने वाले तोमर अपने क्षेत्र के लोगों के हितों का हमेशा खयाल रखते हैं।

शायद इसीलिए तोमर ने एक के बाद एक मुरैना और श्योपुर में दो विशाल नेत्र शिविर आयोजित किए, जिनका लाभ हजारों लोगों को मिला। दोनों जिलों में अलग-अलग ब्लॉकों में लगाए गए शिविरों में 1500 के करीब किसानों और ग्रामीणों की आंखों का नि:शुल्क ऑपरेशन किया गया और उन्हें चश्मे भी प्रदान किए गए। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के अथक प्रयासों से मुरैना जिले में तीन दिवसीय वृहद आई कैम्प आयोजित किया गया। आई कैम्प में कानपुर के सुप्रसिद्ध डॉ. शरद बाजपेयी के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने मुरैना जिले में दो दिनों लगभग 750 ऑपरेशन कर लोगों को नई रोशनी दी है। यह शिविर इफको के सहयोग से लगाया। ओरेठी, पोरसा, अम्बाह और मुरैना में 2 हजार लोग ओपीडी में आए थे, जिसमें से ऑपरेशन योग्य 369 लोग पाए गए, जिनके मुरैना जिला चिकित्सालय में सकुशल ऑपरेशन किए गए। उन मरीजों को अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज कंषाना, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज डंडोतिया, इफको के डायरेक्टर अरूण तोमर, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, अम्बाह विधायक कमलेश जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. योगेशपाल गुप्ता, इफको ग्वालियर के उप महाप्रबंधक एसबी सिंह ने चश्मे, दवाईयां वितरित की एवं उन्हें सकुशल घर के लिए रवाना किया।

इधर जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाडगढ़ में 2 हजार मरीज ओपीडी में आए। जिनमें से 200 को मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। जिनके ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में किए गए। इन मरीजों के ऑपरेशन डॉ. मनीष त्रिवेदी, डॉ. दीपेन्द्र सिंह और डॉ. लोकेश अरोरा ने किए।

श्योपुर में भी सफल रहा शिविर- श्योपुर जिले में बीते 7 सालों में एक साथ जिले भर में कोई बड़ा शिविर नहीं लगाया गया था। इसलिए सांसद नेत्र शिविर से लोगों को बड़ी राहत मिली। जिले के विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण कराने 634 मरीज पहुंचे। इनमें से 151 लोग ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। श्योपुर जिला चिकित्सालय में 1368 मरीज परीक्षण कराने पहुंचे इनमें से 352 को मोतिया बिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया।

सीईओ जिला पंचायत डॉ. गढ़पाले का नवचार बना चर्चा का विषय

सीईओ डॉ. गढ़पाले ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर जानते हैं योजनाओं की हकीकत

मुरैना। जागत गांव हमार

सुविधाओं के युग में जहां अफसर ऑफिस से बहार निकलने में हिचकिचाते हैं, वहीं मुरैना जिले में एक अधिकारी ऐसे भी हैं, जो ग्रामीणों के बीच पहुंचकर चौपाल लगाते हैं। इस चौपाल में ग्रामीण खुद बताते हैं कि उनकी पंचायत में किस योजना का क्या हाल है। इस चौपाल में ग्रामीणों के सामने अधिकारियों की पेशी होती है। इन अधिकारियों को खुद जनता के सवालों के जवाब भी देने होते हैं। सही मायनों में डॉ. गढ़पाले ग्रामीणों को ग्राम स्वराज की ताक से परिचित करवाने का काम कर रहे हैं। जिला पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले ने हाल ही में अंबाह जनपद पंचायत के ऐसाह गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। गुनगुनी धूप में लगाई गई चौपाल में सैकडों की तादद में ग्रामीण रंग-बिरंगे परिधानों में उपस्थित थे। ग्राम चौपाल में विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। मौके पर मनरेगा लेबर बजट में ग्राम पंचायत गोठ के सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई। ग्राम पंचायत भिड़ौसा की प्रगति में कोई सुधार नहीं होने से सचिव, जीआरएस का वेतन रोकने के निर्देश दिय गए। ग्राम पंचायत पुरावसकलां में शत-प्रतिशत प्रगति न आने पर जीआरएस की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई मौके पर ही की गई। वहां का पंचायत निरीक्षक रमेश कुशवाह द्वारा पंचायत के कार्यों में रूचि न लेने के कारण उनका प्रभार सहायक लेखा अधिकारी को देने के निर्देश सीईओ ने दिये। यह सब जनता के सामने जनता की राय के अनुसार ही किया गया।

श्यामुरकलां में भी आयोजित हुई चौपाल

पोरसा जनपद पंचायत के श्यामपुरकलां में भी चौपाल आयोजित की गई। इस चौपाल में भी ग्रामीणों से रूबरू होकर चर्चा करके उनसे ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बंद नल-जल योजना पर पीएचई के उपयंत्री को नोटिस जारी करने, कार्यपालन यंत्री को भौतिक सत्यापन करने के लिये पत्र लिखा गया। समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड की असंतोषजनक प्रगति होने तथा ग्राम पंचायत धर्मगढ़ के जीआरएस को पूर्व बैठक एवं वर्तमान बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण जीआरएस का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। मनरेगा लेबर बजट की निराशाजनक प्रगति होने पर ग्राम पंचायत लालपुरा के पूर्व सरपंच के विरुद्ध जनपद सीईओ को कार्रवाई का प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत लुधावली के पूर्व जीआरएस के जिम्मेदार होने का प्रतिवेदन नवीन जीआरएस तत्काल जनपद सीईओ के माध्यम से भेजने एवं सचिव एवं सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव शीघ्र जनपद सीईओ को भेजने के निर्देश दिऐ। रणवीर तोमर एवं विनोद तोमर का वेतन रोकने के भी निर्देश सीईओ डॉ. गढ़पाले ने दिए। ग्राम पंचायत गढ़िया पोरसा की प्रगति में सुधार न होने के कारण पूर्व एवं वर्तमान दोनों सचिवों का वेतन रोकने, एपीओ बालौठिया को कार्य के प्रति उदासीन रहने, अनुपस्थित रहने आदि के कारण संविदा सेवा समाप्ति का नोटिस देने के निर्देश दिए गए। एपीओ के कार्यों की जांच कराई जाकर वसूली अधिरोपित करने संबंधी निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति प्राप्त होने तक समस्त उपयंत्रियों का वेतन रोकने तथा जिन ग्राम पंचायतों की प्रगति 40 प्रतिशत से कम है, उनके सचिव, जीआरएस के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ ने यह भी कहा कि यदि आगामी बैठक में प्रगति 70 प्रतिशत से कम पाई गई तो सचिवों का निलंबन एवं जीआरएस की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

सीड्स निगम लिमिटेड को मुरैना में मिलेगी जमीन

बैठक में 5 विभागों को भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई है।

मुरैना। संभाग स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की आयोजित बैठक में 5 विभागों को भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई है।

ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर। दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेशनल सीड्स निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली को बीज फार्म विकास के लिए ग्राम पिपरई तहसील मुरैना के अन्तर्गत चाही गई भूमि 219.9 हेक्टेयर में से रकवा 166.858 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की अनुशंसा की गई है।

संभाग स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के अध्यक्ष एवं ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि बैठक में आयुक्त नगर पालिक निगम मुरैना द्वारा शहर में युवा विकास केन्द्र के निर्माण के लिए ग्राम जौरा खुर्द में चाही गई प्रस्तावित 1.453 हेक्टेयर कुल 2083 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपसंचालक अनंत विहारी सडैया द्वारा ग्राम जौरा खुर्द तहसील मुरैना में कृषक छात्रावास निर्माण के लिए चाही गई भूमि 0878 हेक्टेयर आवंटित करने अनुशंसा की गई है। आयुक्त नगर निगम मुरैना द्वारा मुरैना नगर की जलाबर्धन योजना के लिये ग्राम जौरा खुर्द तहसील मुरैना में चाही गई सर्वे नंबर 812 जौरा खुर्द।

अपराधियों को हवालात में कैद करना ड्यूटी और प्रकृति को कैमरे की नजर से देखने के शौकीन हैं योगेंद्र सिंह

वर्दी भी नहीं रोक पाई टीआई साहब का 'जंगल प्रेम'

मुरैना। जागत गांव हमार

आम तौर पर किसी पुलिस इंस्पेक्टर का जिक्र होते ही एक सख्त लहजे वाले, कमर पर पिस्टल कसकर हूटर वाली गाड़ी में बैठकर चलने वाले व्यक्तित्व की कल्पना उभरती है। लेकिन मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं, जिन्हें जंगल, प्रकृति और पशु पक्षियों को कैमरे में कैद करने का शौक है। वे समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का काम भी अपने फोटो ग्राफी के हनुर की मदद से करते हैं। देश के वाइल्ड लाइफ फोटो ग्राफरों के प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा भी हैं ये पुलिस अधिकारी।

हम जिन पुलिस अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं वे मध्य प्रदेश के मुरैना शहर के सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह हैं। श्री सिंह की फोटोग्राफी एक पहचान बनती जा रही है और यही कारण है कि वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के साथ-साथ नेचुरल फोटोग्राफी में भी वे प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। इंस्पेक्टर का कहना है की इस फोटोग्राफी से कभी-कभी बदमाशों को पहचानने और उन्हें पकडने में भी मदद मिलती है। सोशल मीडिया पर भी इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह की फैन फॉलोइंग है। समय-समय पर फोटो शेयर करते रहते हैं और लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं।

मुरैना जिले के कोतवाली थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ योगेंद्र सिंह हमेशा शांति व्यवस्था और बदमाशों में खोंप पैदा करने में सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। कहा जाता है कि जिस इलाके में गुंडों या बदमाशों का आतंक होता है वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को तैनात किया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इस वक्त योगेंद्र सिंह जिस तरीके से अपनी स्वच्छ एवं साफ कार्यप्रणाली के लिए जाने जाते हैं बैसे ही उनकी फोटोग्राफी हमेशा चर्चा में रहती है। इंस्पक्टर योगेंद्र सिंह को फोटोग्राफी का इतना शौक है। यही कारण है कि शानदार फोटोग्राफी के चलते सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।

योगेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का शौक था। लेकिन पुलिस विभाग में नौकरी लगने के बाद भी उनका यह शौक और सपना उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। यही कारण है कि पुलिस की नौकरी में भी वह अपने सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। योगेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस की नौकरी करते समय वे फोटोग्राफी करना नहीं छोड़ते हैं। उनका कहना है कि वह कई बार ऐसे इलाके में भी जाते हैं जहां पर उन्हें फोटोग्राफी करना है और एक फोटो लेने के इंतजार में वह घंटों बिता देते हैं।

किसानों, ग्रामीणों के लिए लगाया नेत्र शिविर सफल

मुरैना। 15 दिसंबर को लॉयन्स क्लब समन्वय मुरैना एवं रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर ने सिविल अस्पताल बानमोर मुरैना में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। बानमोर में आयोजित इस शिविर के प्रति आमजन में विशेष उत्साह देखा गया, बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच कराने पहुंचे।

इस शिविर में 700 से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें दवाई दी गई और इन्हीं में से 150 से अधिक लोगों की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया जिन्हें चिन्हित कर बसों के द्वारा ग्वालियर भिजवाया गया जहां उनका रहना, खाना और ऑपरेशन इत्यादि सब कुछ पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इस शिविर में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, कलेक्टर मुरैना अंकित अष्ठाना, कार्यक्रम के संयोजक राकेश रुस्तमसिंह, लॉयन्स क्लब समन्वय मुरैना की अध्यक्ष रेखा सिंह किरण गुप्ता, मीना गुप्ता, बबिता जैन, रेखा बांदिल, भाजपा बानमोर के मण्डल अध्यक्ष पंजाब सिंह सहित सभी पार्षदगण, नेतागण, कार्यकर्तागण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

सुमावली में 50 बिस्तरीय अस्पताल का होगा उन्नयन

मुरैना। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं प्रदेश के एमपी एग्रो के अध्यक्ष ऐदल सिंह कंषाना के विशेष प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली को 6 बिस्तरीय से बढ़ाकर सिविल अस्पताल का दर्जा देकर 50 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत किया गया है। सिविल अस्पताल सुमावली में बनने से आमजनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक ही मिल सकेंगी।

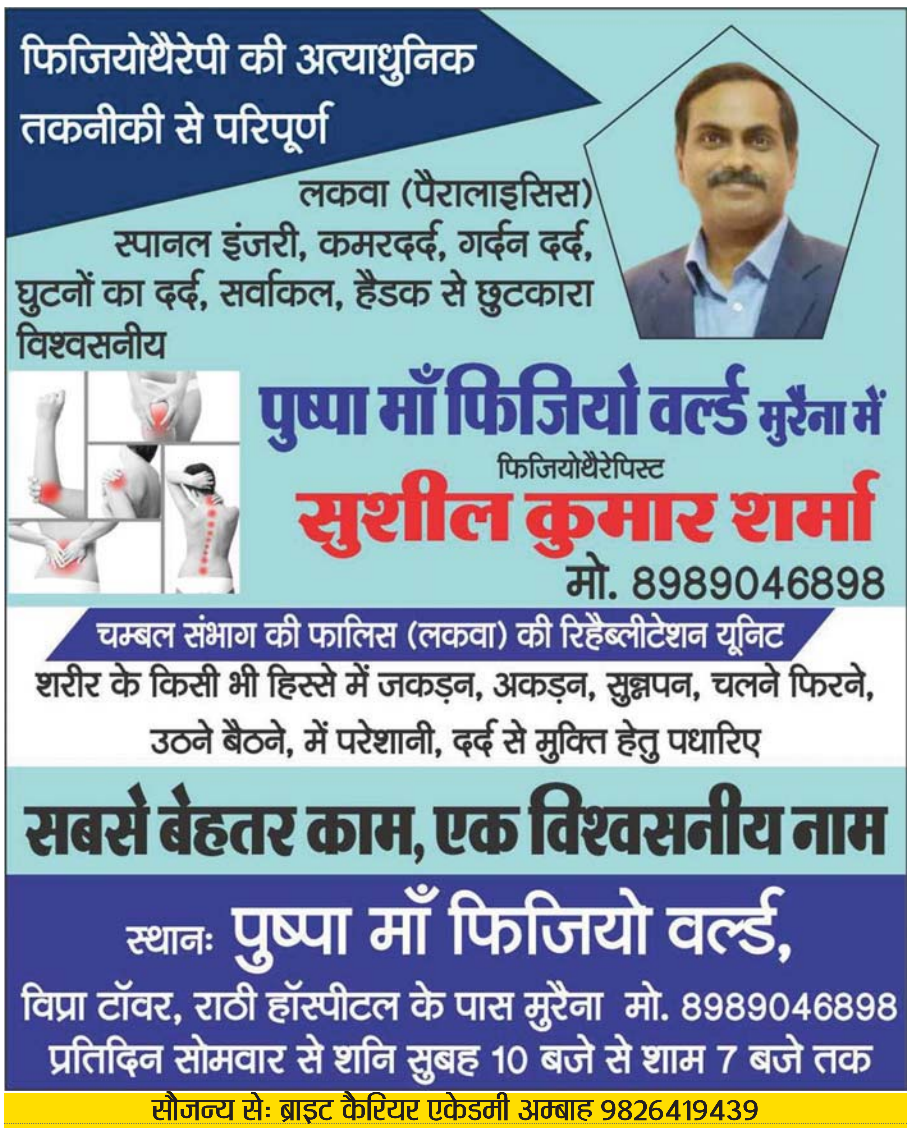

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं 97 विवेकानंद कालोनी, मुरैना मप्र से प्रकाशित।
संपादक: **अवधेश डंडोतिया***, 9425128418, स्थानीय संपादक: **शिवप्रताप सिंह जादौन,** 8085193661 ईमेल-jagatgaon.bpl@gmail.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। संपर्क भोपाल कार्यालय-संपर्क 9229497393,